नक्सलवाद और उसकी चुनौतियाँ

परिचय- 'नक्सल' शब्द की उत्पत्ति पं. बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई तथा बंगाली भाषा में किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति हेतु बारी शब्द का उपयोग किया जाता है। नक्सलवाद कम्यूनिस्ट क्रांतिकारियों के उस अनौपचारिक आंदोलन का नाम है, जो भारतीय कम्यूनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्यल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरूवात की थी। चारू मजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्सेतुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक थे। माओ के विचारों के अनुसार ''क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है''। नक्सली नेता राज्य सत्ता को हथियाकर चीन के नमूने पर एक दलीय शासन पद्धति कायम करना चाहते थे जैसा कि कुछ समय बाद चारू मजूमदार ने उद्घाटित किया।

नक्सलवाद (Naxalism) की उत्पत्ति - भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। ज़मींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था (इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है) और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं।

नक्सलवादियों की मान्यताएँ- नक्सलवादी ये मानते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं।

नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण- केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यत: कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने

दशकों से अनदेखी की है। वे ज़मीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही रोज़गार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मज़बूत बनाया है। जानकार यह मानते हैं कि नक्सलवादियों की सफलता की वज़ह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है।

नक्सलवाद के चरण – नक्सलवाद निम्नांकित चरण हैं-

1. प्रथम चरण (1967 से 1980 तक): इसका प्रथम चरण मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवाद पर आधारित था। इसका मतलब ये ''वैचारिक और आदर्शवादी'' आंदोलन का चरण रहा है। इस चरण में नक्सलवादियों को ''ज़मीनी अनुभव तथा अनुमान की कमी''देखने को मिली। इस चरण में नक्सलियों को एक ''राष्ट्रीय पहचान'' मिली लेकिन वे एक राष्ट्रीय प्रभाव नहीं डाल पाए। 18 मार्च 1967 से जारी इस सशस्त्र गतिविधि को 1971 तक सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इसके बचे नेताओं को भूमिगत होकर काम करना पड़ रहा था। आपातकाल के दौरान् नक्सली आंदोलन खत्म हो गया था। इसके अधिकांश नेता जेल में बंद हो चुके थे।
2. दूसरा चरण (1980 से 2004 तक): ये दौर ज़मीनी अंदाज़ा, ज़रुरत और अनुभव के आधार पर चलने वाला क्षेत्रीय नक्सली गतिविधियों का दौर था। इस चरण में नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास हुआ। इनका क्षेत्रीय प्रभाव और विस्तार भी देखने को मिलता है।
3. तीसरा चरण - (2004 से जारी): इस चरण में नक्सलियों का ''राष्ट्रीय स्वरूप'' उभरा और ''विदेशी संपर्क''बढ़े। और अब नक्सलवाद राष्ट्र की ''सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती''बनकर उभरा। साल 2004 नक्सली संघर्ष की सैन्य और राजनीतिक ताकत और जनाधार के प्रदर्शन का

साल रहा। इस दौरान संसदीय जनतंत्र के ख़िलाफ चुनाव बहिष्कार और नक्सलियों का दक्षिण एशिया के सशस्त्र वामपंथी संगठनों के बीच बढ़ते समन्वय को भी देखा जा सकता था। देश की नक्सली राजनीति में भी साल 2004 में एक नया मोड़ तब आया जब पीपुल्सवार और एमसीसीआई का एकीकरण हुआ और एक नई पार्टी बनी- भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास- सरकार नक्सली चरमपंथ से निबटने के लिये बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय शामिल हैं। सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप नक्सलियों के हौसले कमज़ोर हुए हैं तथा उनके आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेज़ी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48877 किमी. सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। इसके तहत कुल 4072 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है।

सरकार कैसे निपट रही है इन नक्सलियों से - अमूमन कानून-व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है यानी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम संबंधित राज्य का होता है। लेकिन नक्सलवाद की विकटता को देखते हुए साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उसके बाद गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया। साथ ही इससे समस्या से निपटने के लिये बहुआयामी रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा और विकास से जुड़े क़दम और आदिवासी समेत दूसरे कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से जुड़े कदम शामिल हैं। सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है। जून, 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक विशेष पहल की शुरूआत की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित ज़िलों में युवाओं को रोज़गार के लिये प्रशिक्षित किया जा सके। पिछले वर्ष नक्सल समस्या से निपटने के लिये केंद्र सरकर ने आठ सूत्रीय 'समाधान'नाम से एक कार्ययोजना की

शुरुआत की है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित सभी 30 ज़िलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। हिंसा का रास्ता छोड़कर समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए सरकार पुनर्वास की भी व्यवस्था करती है। विकास कामों के अलावा सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ दूसरे अभियान भी चलाये थे:

1. स्टेपेलचेज अभियान: यह अभियान साल 1971 में चलाया गया। इस अभियान में भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने भाग लिया था। इस अभियान के दौरान लगभग 20,000 नक्सली मारे गए थे।
2. ग्रीनहंट अभियान: यह अभियान साल 2009 में छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाया गया था। इस अभियान को यह नाम मीडिया द्वारा दिया गया था।
3. प्रहार: 3 जून, 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य के सुगमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान 'प्रहार'को प्रारंभ किया गया। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तथा इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया। खराब मौसम के कारण 25 जून, 2017 को इस अभियान को रोक दिया गया।

क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही है नक्सल समस्या - दरअसल नक्सलवाद सामाजिक-आर्थिक कारणों से उपजा था। आदिवासी गरीबी और बेरोज़गारी के कारण एक निचले स्तर की जीवन शैली जीने को मज़बूर हैं। स्वास्थ्य-सुविधा के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन क्षेत्रों में असामयिक मौत कोई आश्चर्य की बात नहीं। आदिवासियों का विकास करने के बजाय, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा सेवा और रोजगार देने के बजाय उन्हें परेशान करने के नए-नए कानून बनाए जाते हैं। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की दुर्दशा अभी भी जस की तस बनी हुई है। यकीनन इस तरह की समस्यायों में हमेशा असंतोष के बीज होते हैं, जिनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है। इन्हीं असंतोषों की वजह से ही नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। इससे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं कर रही। लिहाज़ा अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।

नक्सली समस्या से निपटने में प्रशासनिक दिक्कतें क्या-क्या हैं?

1. बुनियादी ढांचा का अभाव

2. प्रशिक्षित मानव संसाधनों और संचार सुविधाओं की कमी
3. नक्सलियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाना
4. केंद्र और राज्यों और राज्यों के बीच आपसी समन्वय का अभाव

शहरी नक्सलवाद क्या है? - पिछले कुछ साल में शहरी नक्सलवाद या अर्बन नक्सलिज़्म शब्द बड़ी तेजी से सामने आया है। शहरी नक्सलवाद से मतलब, उन शहरी आबादी में रहने वाले लोगों से हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर तो नक्सलवादी नहीं है, लेकिन वो नक्सलवादी संगठनों के प्रति और उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कई इन बार इन पर मदद करने का भी आरोप लगता रहा है।

आगे क्या किया जाना चाहिए? - संविधान की पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल की स्थापना की बात की गई है। सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलने के कारण भी इनमें असंतोष पनपता है और नक्सली इसी का फायदा उठाकर आदिवासियों को गुमराह करते हैं। इसी तरह 1996 के पेसा क़ानून, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड जैसे कार्यक्रमों को सही रूप से लागू करने की ज़रूरत है। गरीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी जैसे मसलों पर और बारीकी से काम करना होगा, तभी इस समस्या से निजात मिल पायेगी। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना और हथियार उठा चुके लोगों से बात कर मसले का हल निकालने की कोशिश करनी होगी।

नक्सलवाद बनाम माओवाद:-

कोई माने या न माने माओ लिखित इतिहास के एक महान साम्यवादी सिद्धान्त शास्त्री थे, वे एक क्रांतिकारी, कवि, इतिहासकार, दार्शनिक, प्राचीन विचारों वाले विद्वान तथा सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्धकला के क्षेत्र में पूर्णतावादी थे, **कोहेन** के अनुसार, माओ का क्रांतिकारी प्रवर्तक के रूप में प्रमुख दावा इस तथ्य पर आधारित था कि ग्रामीण क्षेत्रों से लड़े जाने वाले दीर्घकालीक गुरिल्ला युद्धकर्म को व्यवस्थित स्त्रातेजी के प्रतिपादन पर आधारित होना चाहिये। माओ चीनी इतिहास के पारंगत शिष्य थे। इतिहास से उन्होंने यह सीखा कि सफलता प्रमुख रूप से संगठित और अनुशासित प्रयास से प्राप्त की जा सकती है। वह प्राचीन चीनी विचारक सुन जू कि पुस्तक ''आर्ट आफ वार'' से विशेष रूप से प्रभावित थे। ग्रिफिथ ने इस पुस्तक को माओत्से-तुंग के स्त्रातेजिक सिद्धांतों और चीनी सेनाओं के सामरिकी सिद्धांतों का स्रोत माना है। माओ पाश्चात्य विचारकों से भी प्रभावित थे, उनकी रूचि विशेष रूप से रूसी गृह-युद्ध में थी।

उन्होंने क्लाजविट्ज, जोमिनी, माक्र्स-एन्जल्स, लेनिन, आदि की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। परन्तु उन्होंने इन सिद्धांतशास्त्रीयों के विचारों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे अपने देश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक थे। उन्होंने गलत प्रचार के प्रति चेतावनी दी और कहा कि सामान्य रूप से युद्ध के नियमों का अध्ययन करना चाहिये जिनकी उसने बाहरी देशों के नकल की थी। यदि इसका यन्त्रवत नकल व प्रयोग किया जाये जैसे कि रूसी गृहयुद्ध के अनुभव में देखा गया, इनके परिणाम विफलता में परिणित होंगे। संभवतः इसीलिये माओ ने मार्क्स एवं लेनिन के सिद्धांतों में कुछ संशोधन किया। उनका प्रमुख योगदान विशेष रूप से चीन के समान पिछड़े देश के संदर्भ में उनके सिद्धांतों को एशियाई वातावरण के अनुकूल बनाना था। उन्होंने पाया कि औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रान्ति के माक्र्सवादी सिद्धांत का नेतृत्व चीनी परिस्थितियों में अनुपयुक्त था। पदनुसार राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु औद्योगिक सर्वहारा वर्ग की अपेक्षा कृषक वर्ग क्रान्तिकारी संघर्ष की प्रमुख शक्ति बना। बाद में माओ के द्वारा प्रतिपादित विचारों के हो-ची-मिन, गियाप (दोनों वियतनाम), फिदेल कास्त्रा (क्यूबा) तथा अन्य ने अपने सिद्धांतों का आधार बनाया। युद्ध और राजनीति के नजदीकी सम्बन्ध माओ के इस कथन में निर्दिष्ट हैं कि युद्ध को एक क्षण भी राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्लाजविट्ज के विचार का समर्थन करते हुये माओ ने जोर देकर कहा कि युद्ध अन्य साधनों द्वारा राजनीति का पुनरारम्भ होता है। लेनिन ने भी युद्ध को राजनीतिक सम्बन्ध के हिंसात्मक अभिव्यक्ति के रूप में माना था। फ्रूजे ने व्यक्त किया कि राजनीतिक गतिविधि एक नवीन शस्त्र तभी बनेगी जब वह समय समय पर रायफलों और बंदूकों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो गी। और यह सेना की लड़ने की क्षमता में प्रभावकारी वृद्धि करेगी। माओ ने युद्ध को रक्तपात के साथ राजनीति और राजनीति को बिना रक्तपात वाले युद्ध के रूप में वर्णित किया। उनका कथन कि 'राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली की नोक से निकलती है' , को अधिक शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिये। क्रान्तिकारी होते हुये भी माओ ने अहिंसक राजनीतिक शक्ति के महत्व को समझा।

छत्तीसगढ़ की बड़ी नक्सली घटनायेँ

13 मार्च 2018 नक्सलियों ने सुकमा जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एंटी लैंडमाइन वीकल उड़ाया, नौ जवान शहीद

24 अप्रैल, 2017 सुकमा में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवानों पर हमला, 25 जवान शहीद-छह घायल

11 मार्च 2017 सुकमा के भेज्जी इलाके सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर हमला,11 जवान शहीद

12 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजापुर और दरभा घाटी में आईईडी ब्लास्ट में पांच जवानों समेत 14 लोगों की मौत। मरने वालों में सात मतदान कर्मी भी। वारदात में नक्सलियों ने पहली बार एंबुलेंस को निशाना बनाया था। इस एंबुलेंस में सीआरपीएफ के पांच जवानों समेत एंबुलेंस चालक और कंपाउंडर की भी मौत हो गई थी।

11 मार्च 2014 सुकमा जिले के झीरमघाटी में नक्सली हमले में 15 जवान शहीद। इस हमले के बाद नक्सलियों ने एक शहीद जवान के शव में आइईडी लगा दिया था, ताकि जवान जब शव उठाने आएं तो ब्लास्ट हो जाए। जवानों की सतर्कता की वजह से उनकी यह साजिश सफल नहीं हुई।

25 मई 2013 कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने झीरमघाटी में हमला किया। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा लोग मारे गए।

6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की पार्टी को घेरकर हमला कर दिया। इसमें 76 जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है।

12 जुलाई 2009 राजनांदगांव जिले में नक्सलियों ने जवानों को एंबुश में फंसाया। घटना में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी वीके चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए।

अगस्त 2007 दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में मुठभेड़ के दौरान राज्य पुलिस के थानेदार सहित 12 शहीद हो गए।

10 जुलाई 2007 सुकमा जिले के एर्राबोर के उरपलमेटा में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। 23 जवान शहीद हो गए।

उपसंहार- आधुनिक प्रगति के युग में जहां संचार, यातायात एवं अन्य सुविधाएं आम जनता को प्राप्त हुई है उनका फायदा उठाने में नक्सली भी पीछे नहीं हैं। नक्सली इस समय में उच्च स्तर के खतरनाक तरीके अपनाने में लगे हैं। आम जनता, राजनीतिक लोगों तथा सैनिकों आदि की हत्याएं करने का नवीनतम एवं खतरनाक तरीका अपनाने लगे हैं। 11 मार्च 2014 में छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के झीरमघाटी में कांग्रेस दल पर हमले उसमें भयंकर तरह से महेंद्र कर्मा की ह्त्या तथा 2013 में नक्सलवादियों ने झारखण्ड में एक सीआरपीएफ के जवान की हत्या कर उसके पेट में से आंत निकालकर बम सील दिया था। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा तंत्र को हैरान कर दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली कितनी अधिक घिनौनी करतूतों को अंजाम दे सकते हैं। यदि नक्सलियों के हाथों में अत्याधुनिक अधिक संहारक हथियार आ गए तो मानवता के खिलाफ बर्बरता का नंगा नाच होगा, एक भयंकर आपदा होगी। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार को आपसी समन्वयता दिखाते हुए नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जानी चाहिए। यह सच है कि नक्सलवादी विचारधारा सीधे तौर पर सामाजिक शोषण व आर्थिक असमानता से जुड़ी है। इसलिए सरकारों को आँकड़ों की बाजीगरी से अलग रहते हुए इन बिन्दुओं पर ठोस कार्यवाही करने की महत्ती आवश्यकता है। इससे भी बढ़कर विस्थापित आदिवासी समाज के दबे, कुचले व वंचित लोगों के लिए ईमानदारी व प्रतिबद्धता से किए गए सघन विकास कार्य भविष्य में उनको इस नक्सली विचारधारा से बाहर निकालने में संजीवनी का कार्य कर सकते हैं। यह शुभ संकेत है कि शिक्षा तथा अन्य स्रोतों से आई जागरूकता के कारण स्थानीय लोगों ने नक्सलियों का विरोध करना शुरू कर दिया है।